

छत्तीसगढ़ में महिला उद्यमिता, सशक्तिकरण और ग्रामीण परिवर्तन

सुधा प्रधान¹, डॉ. योगमाया उपाध्याय²

शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, आईएसबीएम विश्वविद्यालय, नवापारा (कोसमी), छत्तीसगढ़¹
सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, आईएसबीएम विश्वविद्यालय, नवापारा (कोसमी), छत्तीसगढ़²

सार

छत्तीसगढ़, जो भारत के मध्य में स्थित एक नवगठित राज्य है, वहाँ महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों की भूमिका सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतरण में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। प्रस्तुत समीक्षा शोध-पत्र में उन अध्ययनों का विश्लेषण किया गया है जो यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार सूक्ष्म उद्यमिता महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक पहचान एवं परिवार एवं समाज में निर्णय-शक्ति प्रदान करती है। स्वयं सहायता समूह (SHG), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (CGRLM) जैसी संरचनाओं के माध्यम से महिलाओं को उद्यमशीलता की ओर प्रेरित किया गया है। इस पत्र में 2000 से 2023 तक के 30 से अधिक अध्ययनों का मेटा-विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। शोध का केंद्रीय तर्क यह है कि महिला-संचालित लघु एवं सूक्ष्म उद्यम केवल आर्थिक साधन नहीं हैं, अपितु वे सामाजिक संरचनाओं, लैंगिक भेदभाव, शिक्षा पहुँच एवं स्वास्थ्य जागरूकता पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। छत्तीसगढ़ के जनजातीय एवं ग्रामीण संदर्भों में यह प्रभाव और भी व्यापक एवं गहरा देखा गया है। अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया है कि सशक्त महिला उद्यमी न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समुदाय के सामाजिक संकेतकों को बेहतर बनाने में सहायक होती हैं।

मुख्य शब्द:

महिला उद्यमिता, सूक्ष्म उद्यम, सामाजिक सशक्तिकरण, छत्तीसगढ़, स्वयं सहायता समूह, लैंगिक समानता, ग्रामीण विकास

1. प्रस्तावना

भारत में महिला सशक्तिकरण की यात्रा बहुआयामी रही है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक धरातलों पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना आज नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की प्राथमिक चिंता बन गई है। विशेष रूप से ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों

में, जहाँ लैंगिक असमानता गहरी पैठी हुई है, महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यम परिवर्तन के वाहक बनकर उभरे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य, जो वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश से पृथक होकर बना, अपनी विशिष्ट जनजातीय संरचना, वन-सम्पदा एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कारण इस अध्ययन हेतु एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रस्तुत करता है।

1.1 अध्ययन की पृष्ठभूमि

छत्तीसगढ़ की लगभग 32% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और राज्य के अधिकांश जिले आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। ऐसे में महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण राज्य के समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। NRLM, SGSY, एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है जिन्होंने महिलाओं को सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में सहायता प्रदान की है। बांस शिल्प, तसर रेशम उत्पादन, कृषि-प्रसंस्करण, हस्तशिल्प एवं खाद्य-प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है। यह प्रक्रिया न केवल आर्थिक बदलाव ला रही है, बल्कि पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों को भी पुनर्परिभाषित कर रही है।

1.2 अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध-पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: (i) महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों के सामाजिक सशक्तिकरण पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना, (ii) छत्तीसगढ़ राज्य में इस संदर्भ में किए गए पूर्व अध्ययनों की समीक्षा करना, (iii) लैंगिक समानता, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं निर्णय-भागीदारी पर उद्यमिता के प्रभाव का आकलन करना, तथा (iv) नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना जो महिला उद्यमिता को और अधिक सशक्त बना सकें।

1.3 शोध की महत्ता

यद्यपि भारत में महिला सशक्तिकरण पर विस्तृत साहित्य उपलब्ध है, तथापि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सूक्ष्म उद्यमों एवं सामाजिक सशक्तिकरण के अंतःसंबंध पर केंद्रित मेटा-विश्लेषणात्मक शोध की कमी देखी जाती है। इस शोध-पत्र में 2000 से 2023 तक के अध्ययनों का समेकित विश्लेषण करके यह समझने का प्रयास किया गया है कि सूक्ष्म उद्यमिता किस प्रकार बहुआयामी सशक्तिकरण को संभव बनाती है। यह शोध न केवल शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य सरकार, NGO एवं विकास संस्थाओं को भी नीतिगत दिशा-निर्देश प्रदान कर सकता है।

2. साहित्य सर्वेक्षण

महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक सशक्तिकरण के बीच के संबंध पर वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त शोध हुआ है। कबीर [1] ने 1999 में महिला सशक्तिकरण को तीन मूलभूत संसाधन, अभिकर्ता एवं उपलब्धि में विभाजित किया और तर्क दिया कि आर्थिक स्वावलंबन सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। चेन एट अल. [2] ने माइक्रोफाइनेंस एवं महिला सशक्तिकरण के अंतःसंबंध को स्पष्ट करते हुए बताया कि ऋण की प्राप्ति से महिलाओं की व्यावसायिक भागीदारी बढ़ती है। मेयौक्स [3] ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया का विस्तृत विश्लेषण किया और पाया कि सामूहिक उद्यमिता व्यक्तिगत प्रयासों से अधिक प्रभावी है।

भारत के संदर्भ में दत्ता और गेली [4] ने दिखाया कि स्वयं सहायता समूहों में भागीदारी से महिलाओं की आत्मविश्वास एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। नायर [5] ने केरल एवं आंध्रप्रदेश के अनुभव का उल्लेख करते हुए माइक्रोफाइनेंस को सामाजिक परिवर्तन के औजार के रूप में प्रस्तुत किया। सिंह और लाल [6] ने मध्यप्रदेश में हाथकरघा उद्योग में महिला उद्यमियों का अध्ययन किया और पाया कि पारंपरिक शिल्पों में महिलाओं की भागीदारी से उनकी सामाजिक स्थिति खुलती है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में शर्मा एवं त्रिपाठी [7] ने बस्तर जिले में आदिवासी महिला उद्यमियों का अध्ययन किया और पाया कि वनोपज आधारित किशोरों ने महिलाओं की आय में औसत 40% की वृद्धि की। मिश्रा [8] ने रायपुर एवं दुर्ग के शहरी क्षेत्रों में महिला-संचालित खाद्य प्रसंस्करण किशोरों का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि सहकर्मियों से महिलाओं की निर्णय-भागीदारी में सुधार आता है। वर्मा एवं अन्य [9] ने सीजीआरएलएम के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों का मूल्यांकन किया और पाया कि समूह-ऋण से जरूरतमंद महिलाओं में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

पांडे [10] ने सरगुजा एवं जशपुर में वन आधारित सूक्ष्म पोषक तत्वों का अध्ययन किया, जिसमें तेंदूपत्ता संग्रह, लाख उत्पादन एवं वनौषधि कंपनी में महिलाओं की भूमिका प्रमुख थी। उन्होंने पाया कि पारिवारिक हिंसा में आर्थिक भागीदारी की कमी है। राव और सिंह [11] ने छत्तीसगढ़ में स्वयं सहायता समूह और सामाजिक क्षेत्र के निर्माण का अध्ययन करते हुए कहा कि समूह-सदस्यता से महिलाओं के सामाजिक नेटवर्क का विस्तार होता है। गुप्ता [12] ने राज्य में तसर रेशम उद्योग में महिला शिल्पकारों का अध्ययन किया और पाया कि यह उद्योग महिलाओं को वर्षभर रोजगार प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में ब्रश एट अल. [13] महिला उद्यम के तीन आयाम व्यक्तिगत संदर्भ, सामाजिक संदर्भ और व्यावसायिक संदर्भ की पहचान। डी वीटा एट अल. [14] पूर्वोत्तर में महिला उद्यमिता की संभावनाओं का विश्लेषण किया गया जिसमें वित्त तक पहुंच, सामाजिक एवं निजीकरण कौशल शामिल



प्रमुख थे। वीक्स एंड सेइलर [15] ने ग्रामीण उद्यमों और सामाजिक संबंधों के बीच के संबंध को स्थापित किया। UNDP [16] की 2019 की रिपोर्ट में महिला-नेतृत्व वाले सहायक को SDG-5 (भाषा) का प्रमुख माध्यम बताया गया है।

घरेलू शोध में सिन्हा [17] ने उत्तर छत्तीसगढ़ में ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों का अध्ययन किया। कुमार और तिवारी [18] ने माइक्रोफाइनेंस एवं महिला संविधान के बीच सकारात्मक सहसंबंध की पुष्टि की। जैन [19] ने स्वर्णजय ग्रामंती संगम योजना के अंतर्गत महिला ईसाई का अध्ययन किया। गर्ग [20] ने डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं महिला उद्यम के अंतःसंबंध का विश्लेषण किया। भट्ट और नायक [21] ने सेवा के अनुभव के आधार पर सामूहिक उद्यमिता के मॉडल का प्रस्ताव रखा।

चक्रवर्ती [22] ने छत्तीसगढ़ के मैदानी एवं पहाड़ी इलाकों में महिला उद्यमिता के स्वरूप की तुलना की और पाया कि पहाड़ी इलाकों में बाधाएं अधिक हैं। भट [23] ने माइक्रोफाइनेंस की आंशिक भूमिका का आकलन करते हुए पाया कि महिला उद्यमिता के लिए बड़ी चुनौती हैं। त्रिपाठी और सिंह [24] ने छत्तीसगढ़ में बांस शिल्प का अध्ययन किया। पटेल [25] ने महिला उद्यमिता एवं बाल-शिक्षा नामांकन दर के बीच सकारात्मक संबंध पाया। ठाकुर [26] ने राज्य में महिला-संचालित खाद्य पदार्थों का अध्ययन किया। गोयल और रानी [27] ने पीएमईजीपी एवं महिला सिद्धांत का विश्लेषण किया। श्रीवास्तव [28] ने सूक्ष्म उद्यम एवं स्वास्थ्य व्यवहार के बीच संबंध की जांच की। पांडा [29] ने जनजातीय महिला उद्यमियों की विशेष झलकियाँ देखीं। अंत में, विश्व बैंक [30] की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ सहित भारतीय राज्यों में महिला उद्यमिता की स्थिति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध-पत्र एक द्वितीयक डेटा-आधारित समीक्षा एवं मेटा-विश्लेषण है। शोध में 2000 से 2023 के बीच प्रकाशित उन समुदायों को सम्मिलित किया गया है जो महिला साक्षरता, सूक्ष्म उद्यम एवं सामाजिक सशक्तिकरण के विषयों पर केंद्रित हैं। डेटा संग्रह के लिए Google Scholar, Scopus, PubMed, JSTOR, IndMED एवं शोधगंगा जैसे डेटाबेस का उपयोग किया गया। खोज शब्दों में 'महिला साक्षरता', 'सूक्ष्म उद्यम', 'सामाजिक सशक्तिकरण', 'स्वयं सहायता समूह', 'छत्तीसगढ़', 'महिला सूक्ष्म उद्यम', 'सामाजिक सशक्तिकरण', 'SHG', 'NRLM', 'छत्तीसगढ़' आदि सम्मिलित थे। समावेशन मानदंड में वैक्टर-समीक्षित पत्रिकाएँ, सरकारी रिपोर्ट, PhD शोध-प्रबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रकाशित रिपोर्ट शामिल थीं।

शोध-पत्रों के चयन में PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) प्रश्नावली का अनुसरण किया गया। प्रारंभिक खोज में 185 अध्ययन प्राप्त हुए जिनमें से शीर्षक एवं सार के आधार पर 87 का चयन किया गया। पूर्ण पाठ समीक्षा के पश्चात 30 अध्ययन अंतिम विश्लेषण में सम्मिलित किए गए। बहिष्करण मानदंड में अप्रासंगिक भौगोलिक क्षेत्र, अनुपलब्ध पूर्ण पाठ, एवं पर्याप्त पद्धतिगत विवरण का अभाव शामिल था। विश्लेषण में थीमैटिक परिवहन विधि का उपयोग किया गया जिसमें सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं राजनीतिक को समकक्ष में विभाजित किया गया।

डेटा के लंबित विश्लेषण के लिए विषयवार परिवहन एवं तुलनात्मक विश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया गया। छत्तीसगढ़-विशिष्ट प्रक्रियाओं को अलग से चिह्नित कर उनकी विशेष विशेषताओं का विश्लेषण किया गया। प्रत्येक अध्ययन का मूल्यांकन तीन आयामों पर किया गया: (अ) अध्ययन की पद्धतिगत प्रगति, (ब) आयामों की सामान्यीकृत क्षमता, एवं (स) नीतिगत कार्यप्रणाली। इस त्रिकोणीय मूल्यांकन से खोज की वैधता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित की गई। शोध की सीमाओं में प्राथमिक डेटा का अभाव एवं भाषाई पूर्वाग्रह (अधिकांश अध्ययन अंग्रेजी में) सम्मिलित हैं।

4. पूर्व कार्यों का समालोचनात्मक विश्लेषण

पूर्व विकास के समालोचनात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि महिला साक्षरता एवं सामाजिक सशक्तिकरण के बीच संबंध की व्याख्या में विभिन्न विचलन हैं। एक ओर, मेयौक्स [3] एवं दत्ता और गेली [4] जैसे शोधकर्ता तर्क देते हैं कि SHG सदस्यता स्वतः सशक्तिकरण की सुनिश्चित नहीं है यदि समूह की प्रश्नावली पितृसत्तात्मक सामाजिक ढाँचे के भीतर ही सीमित रहें तो वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं। दूसरी ओर, शर्मा एवं त्रिपाठी [7] एवं मिश्रा [8] के अध्ययन छत्तीसगढ़ में सकारात्मक बदलाव दर्ज करते हैं, लेकिन उनके नमूने नवीन छोटे हैं जिससे सामान्यीकरण सीमित होता है।

व्यवस्थागत दृष्टि से देखें तो अधिकांश अध्ययन साक्षात्कार एवं केस-स्टडी पर आधारित हैं जो लंबित दृष्टि से समृद्ध हैं, लेकिन सांख्यिकीय प्रमाण सीमित हैं। राव एवं सिंह [11] का सामाजिक पूंजी मॉडल एवं पांडे [10] का वन-उद्यम अध्ययन उल्लेखनीय है, लेकिन इनमें दीर्घकालिक अनुवर्ती अध्ययन का अभाव है। कुमार & तिवारी [18] ने माइक्रोफाइनेंस के सकारात्मक प्रभाव की पुष्टि की, लेकिन भट [23] ने यह प्रश्न उठाया कि उच्च ब्याज अनुमानित महिलाओं को ऋण-जाल में फँसा सकती हैं। यह विरोधाभासी निष्कर्ष नीतिगत विक्रेताओं को जटिल बनाते हैं।



छत्तीसगढ़-विशिष्ट शोध में भौगोलिक विश्लेषण भी देखा गया है। अधिकांश अध्ययन रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर जिलों तक सीमित हैं, जबकि बस्तर, सरगुजा एवं जशपुर जैसे दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों पर पर्याप्त शोध नहीं हुआ है। पांडा [29] ने जनजातीय महिला उद्यमियों की विशेष पिक्सल को आयताकार किया, लेकिन गहन जातीय संरचनाओं की कमी है। गर्ग [20] ने डिजिटल साक्षरता का उल्लेख किया, लेकिन ग्रामीण छत्तीसगढ़ में डिजिटल विभाजन की समस्या को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। इन सभी अंतरालों को भरने की आवश्यकता भविष्य के शोध हेतु एक महत्वपूर्ण शीर्षक प्रस्तुत करती है।

5. चर्चा

समीक्षित साहित्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ में महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यम सामाजिक सशक्तिकरण के बहुआयामी माध्यम बन रहे हैं। आर्थिक स्वावलंबन से महिलाओं की परिवार एवं समुदाय में निर्णय-शक्ति बढ़ी है। स्वयं सहायता समूहों ने न केवल ऋण उपलब्ध कराया बल्कि सामूहिक पहचान एवं नेतृत्व क्षमता का विकास भी किया है। तसर रेशम, बांस शिल्प एवं वनोपज आधारित उद्यम स्थानीय संसाधनों पर आधारित हैं जो सतत विकास की दृष्टि से अधिक उपयुक्त हैं।

हालांकि कई चुनौतियाँ भी बनी हुई हैं। बाज़ार संपर्क का अभाव, कौशल प्रशिक्षण की अपर्याप्त सुविधाएँ, वित्तीय साक्षरता की कमी एवं सामाजिक मानदंडों का दबाव महिला उद्यमियों की प्रगति में बाधा डालते हैं। डिजिटल माध्यमों का प्रभावी उपयोग, सरकारी योजनाओं की बेहतर पहुँच एवं मार्केटिंग सहायता से इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं की परंपरागत दक्षताओं को आधुनिक उद्यमिता से जोड़ने की आवश्यकता है जिससे सांस्कृतिक पहचान एवं आर्थिक विकास दोनों साथे जा सकें।

6. निष्कर्ष

प्रस्तुत समीक्षा शोध-पत्र इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि छत्तीसगढ़ में महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यम सामाजिक सशक्तिकरण के शक्तिशाली साधन हैं। ये उद्यम न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करते हैं, बल्कि लैंगिक असमानता को कम करने, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा सामाजिक निर्णय-प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में भी योगदान देते हैं। NRLM एवं CGRLM जैसी योजनाओं ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है, परंतु अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

भविष्य के शोध हेतु यह सुझाव है कि छत्तीसगढ़ के दूरस्थ जनजातीय जिलों में दीर्घकालिक अनुदैर्ध्य अध्ययन किए जाएँ जो उद्यमिता एवं सशक्तिकरण के कारण-परिणाम संबंध को और स्पष्ट कर सकें।

नीति-निर्माताओं को चाहिए कि वे महिला उद्यमियों के लिए एकीकृत सहयोग तंत्र विकसित करें जिसमें वित्त, बाज़ार, प्रशिक्षण एवं डिजिटल सहायता सम्मिलित हो। तभी महिला सशक्तिकरण का स्वप्न पूर्णतः साकार हो सकेगा।

संदर्भ सूची

- [1] एन. कबीर, "संसाधन, एजेंसी, उपलब्धियां: महिलाओं के सशक्तिकरण को मापने पर विचार," डेवलपमेंट एंड चेंज, वॉल्यूम 30, नंबर 3, पेज 435-464, 1999.
- [2] एम. चेन, आर. झाबवाला, आर. कानबुर, और सी. रिचर्ड्स, गरीबों के सदस्यता-आधारित संगठन। लंदन: रूटलेज, 2007.
- [3] एल. मेयॉक्स, "नकारात्मक पहलुओं से निपटना: कैमरून में सामाजिक पूंजी, महिलाओं का सशक्तिकरण और माइक्रो-फाइनेंस," डेवलपमेंट एंड चेंज, वॉल्यूम 32, नंबर 3, पेज 435-464, 2001.
- [4] पी. दत्ता और आर. गैली, "सामाजिक उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण: भारत में एक महिला सहकारी समिति का केस स्टडी," एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी एंड प्रैक्टिस, वॉल्यूम 36, नंबर 3, पेज 569-587, 2012.
- [5] टी. एस. नायर, "भारत में माइक्रोफाइनेंस को संस्थागत बनाना: रणनीतिक मुद्दों का अवलोकन," इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 36, नंबर 4, पेज 399-404, 2001.
- [6] आर. सिंह और बी. लाल, "मध्य प्रदेश के हथकरघा उद्योग में महिला उद्यमिता: चुनौतियां और अवसर," इंडियन जर्नल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज, वॉल्यूम 5, नंबर 2, पेज 67-74, 2014.
- [7] पी. शर्मा और ए. त्रिपाठी, "बस्तर, छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिला उद्यमी: वन-आधारित उद्यमों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण," जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वॉल्यूम 35, नंबर 1, पेज 45-62, 2016.
- [8] एस. मिश्रा, "शहरी छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नेतृत्व वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्यम: रायपुर और दुर्ग का अध्ययन," एशियन जर्नल ऑफ बिनेस स्टडीज, वॉल्यूम 22, नंबर 3, पेज 112-128, 2016.
- [9] आर. के. वर्मा, ए. साहू, और पी. गुप्ता, "महिलाओं के सशक्तिकरण पर CGRLM का प्रभाव: छत्तीसगढ़ में SHG सदस्यों का एक अध्ययन," इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम 72, नंबर 2, पेज 89-105, 2017.

- [10] डी. पांडे, "छत्तीसगढ़ के सरगुजा और जशपुर में जंगल पर आधारित आजीविका और महिलाओं का सशक्तिकरण," सोसाइटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वॉल्यूम 31, नंबर 4, पेज 412-427, 2018.
- [11] एस. राव और ए. सिंह, "स्वयं-सहायता समूह और सामाजिक पूंजी का निर्माण: छत्तीसगढ़ से प्रमाण," जर्नल ऑफ़ डेवलपमेंट स्टडीज़, वॉल्यूम 54, नंबर 11, पेज 2065-2081, 2018.
- [12] ए. गुप्ता, "छत्तीसगढ़ में तसर रेशम उद्योग और महिला कारीगर: आजीविका, पहचान और सशक्तिकरण," इंडियन जर्नल ऑफ़ लेबर इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम 61, नंबर 3, पेज 215-232, 2018.
- [13] सी. जी. ब्रश, ए. डी ब्रुइन, ई. गेटवुड, और सी. हेनरी, महिला उद्यमी और विकास के लिए वैश्विक माहौल। चेल्टनहैम: एडवर्ड एल्गर, 2010.
- [14] एल. डी वीटा, एम. मारी, और एस. पोगोसी, "विकासशील देशों में और वहां से महिला उद्यमी: साहित्य से प्रमाण," यूरोपियन मैनेजमेंट जर्नल, वॉल्यूम 32, नंबर 3, पेज 451-460, 2014.
- [15] जे. वीक्स और डी. सीलर, महिला उद्यमिता और सूक्ष्म उद्यम: चुनौतियों का सामना करना। वाशिंगटन डीसी: OECD, 2001.
- [16] UNDP, मानव विकास रिपोर्ट 2019: आय से परे, औसत से परे, आज से परे। न्यूयॉर्क: यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, 2019.
- [17] वी. सिन्हा, "उत्तरी छत्तीसगढ़ में ग्रामीण महिलाओं की आजीविका: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण," कंटेंपरेरी वॉयस ऑफ़ दलित, खंड 11, अंक 1, पृष्ठ 55-67, 2019.
- [18] ए. कुमार और पी. तिवारी, "माइक्रोफाइनेंस और महिला सशक्तिकरण: छत्तीसगढ़ से अनुभवजन्य साक्ष्य," फाइनेंस इंडिया, खंड 33, अंक 2, पृष्ठ 565-582, 2019.
- [19] बी. जैन, "SGSY और महिला लाभार्थी: छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में एक मूल्यांकन," जर्नल ऑफ़ रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, खंड 7, अंक 2, पृष्ठ 1-9, 2019.
- [20] पी. गर्ग, "मध्य भारत में डिजिटल तकनीक और महिला उद्यमिता," जर्नल ऑफ़ एंटरप्राइजिंग कम्युनिटीज़, खंड 14, अंक 3, पृष्ठ 395-413, 2020.
- [21] ई. भट्ट और आर. नायक, कलेक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप: द SEWA मॉडल. अहमदाबाद: SEWA पब्लिकेशन्स, 2005.
- [22] एस. चक्रवर्ती, "छत्तीसगढ़ के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में महिला उद्यमिता: एक तुलनात्मक अध्ययन," जर्नल ऑफ़ एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, खंड 9, अंक 1, पृष्ठ 23-34, 2020.

- [23] ओर. भट, "ब्याज दरें, ऋणग्रस्तता और महिला उद्यमी: छत्तीसगढ़ में MFI उधारकर्ताओं से साक्ष्य," अर्थशास्त्र: इंडियन जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च, खंड 9, अंक 3, पृष्ठ 1-12, 2020.
- [24] ए. त्रिपाठी और आर. सिंह, "छत्तीसगढ़ में बांस शिल्प क्लस्टर और महिला कारीगर: बाजार संपर्क और सशक्तिकरण," इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ रूरल मैनेजमेंट, खंड 17, अंक 2, पेज 145-163, 2021.
- [25] एम. पटेल, "महिला उद्यमिता और बच्चों की शिक्षा में नामांकन: ग्रामीण छत्तीसगढ़ से अनुभवजन्य प्रमाण," जर्नल ऑफ़ फैमिली एंड इकोनॉमिक इश्यूज़, वॉल्यूम 42, नंबर 1, पेज 112-125, 2021.
- [26] एन. ठाकुर, "छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नेतृत्व वाले खाद्य उद्यम और सामाजिक-आर्थिक बदलाव," जर्नल ऑफ़ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वॉल्यूम 58, नंबर 9, पेज 3315-3324, 2021.
- [27] एस. गोयल और एम. रानी, "PMEGP लाभार्थी और लिंग: छत्तीसगढ़ में एक आलोचनात्मक मूल्यांकन," योजना, वॉल्यूम 66, नंबर 4, पेज 30-35, 2022.
- [28] ए. श्रीवास्तव, "सूक्ष्म उद्यम, स्वास्थ्य व्यवहार और सामाजिक पूंजी: छत्तीसगढ़ में महिला SHG सदस्यों से मिली जानकारी," हेल्थ एंड प्लेस, वॉल्यूम 73, पेज 102741, 2022.
- [29] एन. पांडा, "आदिवासी महिला उद्यमी: छत्तीसगढ़ में विशेष चुनौतियां और लचीलेपन की रणनीतियां," जेंडर, प्लेस एंड कल्चर, वॉल्यूम 29, नंबर 5, पेज 631-648, 2022.
- [30] विश्व बैंक, महिला उद्यमिता को सक्षम बनाना: उद्यमियों में लिंग के पहलू को शामिल करना हिप पॉलिसी। वॉशिंगटन डीसी: वर्ल्ड बैंक ग्रुप, 2023।